शिक्षा माफिया के....

कि किस तरह राज्य का शिक्षा मंत्री सारे फैसले प्राइवेट स्कूलों के हक में ले रहा है। डीपीएस के नाम से शहर में दो स्कूल चल रहे हैं। डीपीएस सेक्टर 81 ग्रेटर फरीदाबाद और डीपीएस मथुरा रोड फरीदाबाद ने मनमानी और बदमाशी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। दोनों स्कूलों में सारी सालाना फीस वसूली गई। अप्रैल से अभी तक की आईटी फीस वसूली गई।

कुछ अभिभावकों ने सीएम विंडो पर की गई शिकायत में लिखा है कि डीपीएस का मैनेजमेंट उनकी ईमेल का जवाब तक नहीं देता। अभिभावकों ने वसूली गई फीस का ब्यौरा मांगा लेकिन वो भी नहीं दिया गया। जिन अभिभावकों ने अभी तक पूरी सालाना फीस नहीं जमा कराई, उनके बच्चों को बेइज्जत कर आनलाइन क्लास लेने से रोक दिया गया है। कुछ स्कूलों ने कोविड19 के बावजूद फीस तक बढ़ा दी। इस संबंध में मॉर्डन डीपीएस की बदमाशी की खबरें मजदूर मोर्चा लगातार छाप रहा है। इस स्कूल के खिलाफ जांच के नाम पर खानापूर्ति करके मामला दबा दिया गया। अभिभावकों का कहना है कि जब बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं तो उनसे ट्यूशन फीस के अलावा बाकी फीस क्यों वसूली गई और क्यों मांगी जा रही है। कुछ स्कूलों ने तो सारी फीस लेने के बाद टोटल पैसे की रसीद पकड़ा दी, जिसमें यह साफ नहीं है कि किस मद में कितना पैसा लिया गया।

टीचरों का वेतन आधा, कुछ की नौकरी गई

प्रधानमंत्री मोदी के सूत्र वाक्य आपदा में अवसर को फरीदाबाद के प्राइवेट स्कूलों ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। छोटे ही नहीं बल्कि नामी-गिरामी स्कूलों ने तमाम टीचरों को नौकरी से निकाल दिया है। जिन कुछ टीचरों को रखा है उनका वेतन आधा कर दिया गया है। इन टीचरों की सैलरी आनलाइन क्लास के बहाने से कम की गई है। कोरोना काल में बसों तक की फीस वसूलने वाले स्कूल अपने टीचरों को आधी सैलरी दे रहे हैं। नहरपार एक स्कूल से हटाई गई एक महिला टीचर ने बताया कि शिक्षा माफिया बच्चों से भी ज्यादा शोषण टीचरों का कर रहा है। हम लोगों का वेतन पहले से ही कम होता है। लेकिन जब कोरोना फैला तो वो वेतन आधा कर दिया गया। ज्यादातर स्कूलों में टीचरों की संख्या खर्चे घटाने के लिए कम कर दी गई है। कोरोना में सबसे बुरी दशा प्राइवेट टीचरों की है। जो टीचर ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर खर्चे निकाल रहे थे, उनके ट्यूशन में बच्चे भी कम हो गए हैं, क्योंकि अभिभावक मोटी फीस भरें या ट्यूशन लगाएं। प्राइवेट स्कूल टीचरों का कोई संगठन न होने की वजह से इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इनकी न खट्टर सरकार में कोई सुनता है और न ही स्कूल माफिया सुनने को तैयार है।

काम की खबरें

दुकानों का किराया माफ

हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर स्थित दुकानों का पूरा किराया माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही, 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए भी ऐसी दुकानों का 50 प्रतिशत किराया माफ किया जाएगा।

गेहूं की नई किस्म विकसित

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की WH 1270 उन्नत किस्म विकसित की है। इस किस्म को भारत के उत्तर-पश्चिम मैदानी इलाकों के लिए अनुमोदित किया गया है।

पेंशनधारकों को बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 तक करने का निर्णय लिया है। पहले अंतिम तिथि 30 नवम्बर थी।

हज यात्रा आवेदन की तारीख बढ़ी

हरियाणा राज्य हज कमेटी ने 2021 में हज यात्रा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि को 10 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 कर दी है। इच्छुक आवेदक हज कमेटी इंडिया मुम्बई की वेब साइट http://hajcommittee.gov.in पर हज कमेटी के मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कम्पार्टमेंट परीक्षा 16 जनवरी को

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,भिवानी द्वारा सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी(शैक्षिक)कम्पार्टमेंट की एक दिवसीय परीक्षा का आयोजन 16 जनवरी, 2021 को करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा का तिथि-पत्र बोर्ड की अधिकारिक वैबसाईट http://bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है।

मोनोपोली ओर किसान बिल

मार्किट आधारित पूंजीवादी व्यवस्था मे कंपीटिशन कीमतों को कंट्रोल करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस उपलब्ध कराने का आधारभूत नियम है। एक अमेरिकी उद्योगपति था एंड्रू कार्नेगी। आज के सबसे अमीर आदमी अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बिजो से अगर वक़्ती तुलना करें तो दुगना अमीर।

उसका स्टील का व्यापार था। एक ओर तेल बेचने वाला था रॉकफ़ेलर उससे भी अमीर। जब ये उद्योगपति व्यापार मे बेहिसाब अमीर हो गए तो अमेरिकी सरकार ने उन्हें समानता या कंपीटिशन के लिए खतरा मानते हुए उनकी कंपनियो के टुकड़े टुकड़े कर दिये। ऐसा ही अमेरिकन टोबैको कंपनी के साथ किया।

अभी कुछ सालो पहले अमेरिका की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी एटी × टीके भी 7 टुकड़े कर दिए गए। ऐसा ही केस अमेरिकन कोर्ट बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आदि के खिलाफ लेकर आई। जब जब कंपनियों ने एकाधिकार किया तो सिस्टम को ईमानदारी से चलाने, ग्राहकों को बचाने के लिए वहां सरकार ने उद्योगपतियों/कंपनियों के खिलाफ खड़े होकर संपत्ति पर एकाधिकार घटाया।

अभी भारत मे कुछ कानूनों को लेकर कंपनियो/सरकार के खिलाफ एक जनप्रतिरोध जारी है। किसानों को कहा जा रहा है मार्किट मे उतरो। खुद बेचो। अच्छी बात है। भारत के 82 प्रतिशत किसान ढाई एकड़ से छोटे है। जानते है उन्हें किसका मुकाबला करना है? 1,40,00,00,00,000/- का तो फोरचून नामक सिंगल ब्रांड है, अडानी-विल्मर का। आटे मे मसाले मिलाकर मैग्गी या आटे मे दूध मिलाकर सेरेलक बनाने वाली नेस्ले की नेट वर्थ है 24,00,00,00,000/-। 2 हजार से ऊपर तो उसके ब्रांड्स है। गांव मे आम पशुपालक खर्चा ओर मेहनत करके 27 रुपए लीटर दूध बेचता है जबकि अमूल वही दूध बिना गाय भैंस पाले शहरियों को 54 रुपए लीटर बेच देता है, उसकी हैसियत है 52 हजार करोड़।

किसानों क्या सोच रहे हो? कृषि मार्किट पूंजीवाद के लिए खोल दिया गया है। तुम्हे लगता है समानता का अधिकार देने के लिए सरकारें इन कंपनियों/व्यापारियों के खिलाफ खड़ी होंगी? दुनिया मे संपत्ति की सबसे अधिक असमानता रूस मे है। मतलब मुट्ठीभर कुलीनों के पास सारे देश की संपत्ति है। और मोदी से लड़ने वाले आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने 4 साल पहले कहा था कि अगर भारत चंद व्यापारियों द्वारा कब्जाया गया कुलीनतंत्र नही है तो फिर क्या है? ओर 4 सालो मे तो अम्बानी अडानी उस समय से भी कई गुणा बढ़ चुके।

ओर तुम्हारी बात उठाने के लिए कोई नही होगा? नही क्योंकि वहां भी मोनोपोली है। 80 करोड़(टोटल का 95 त्न) टीवी देखने वाले दर्शकों तक अकेले रिलायंस के 76 टीवी चैनल्स की पहुंच है। आंदोलन मे किसानों की दुर्गति से आहत होकर संत राम सिंह ने जान दे दी। कहीं कोई चर्चा? बल्कि अम्बानी ने तो पिछले साल मोदी सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने की हिमायत की थी। यें जब चाहे इंटरनेट बंद करके आंदोलन को विमर्श से ही पूरी तरह गायब कर दें।

बस मोदी जी के आशीर्वाद से ढाई एकड़ जोतने वाले किसान को इन्ही नेस्ले, अमूल, फार्च्यून, रिलायंस से कॉम्पिटिशन करना है।

- महक सिंह तरार

ट्रेड यूनियन संघर्ष का सच्चा किस्सा : झूठ ही सबसे बड़ा सच

चन्द्रभूषण

मार्खेज की 'वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड' ने दुनिया को कई अमर कथापात्र दिए हैं, लेकिन जो चेहरा आजकल मेरे जेहन में थरथराता रहता है, वह इसके एक अनजाने से पात्र जोस अर्कादियो सेगुंडो का है। कहानी की कुल सात पीढ़ियों में चौथी यानी ठीक बीच में आया यह नौजवान किसी प्रतिबद्धतावश नहीं, सामान्य सहानुभूति के तहत ही अपनी पुश्तैनी बस्ती मकोंडो के पास अमेरिकी मालिकाने वाले एक केला बागान के मजदूरों की हड़ताल से जुड़ जाता है।

यहां कथा को यथार्थ से अलगाना जरूरी है। यह दक्षिणी अमेरिका के एक वास्तविक ट्रेड यूनियन संघर्ष का किस्सा है, जिसकी परिणति महाद्वीप के सबसे बड़े और रहस्यमय जनसंहार के रूप में हुई। 5-6 दिसंबर 1928 को कोलंबिया के सिएनागा कस्बे में हुई इस घटना का कहीं कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। मृतकों की संख्या 9 से लेकर 3000 तक बताई जाती है, हालांकि कुल कितने मजदूर इस सरकारी दमन में मारे गए, यह आज भी पक्का नहीं है।

कहानी पर लौटें तो जोस अर्कादियो अकेले में मगन रहने वाला जहां-तहां भटकता एक दुबला-पतला, पढ़ाकू-सा नौजवान है, जिसका अकेला शौक मुर्गे लड़ाने का है। जिस केला बागान की बात यहां हो रही है, उसे मि. जैक ब्राउन ने उसके घर पर ही विचार-विमर्श के बाद लगाया है, सो मैनेजमेंट के प्रति उसके मन में कोई शत्रुता नहीं है। बस, मजदूर परेशान हैं, औरों की तरह उन्हें भी दिन भर खटने के बाद रात को खाना खाकर चैन से सोने का मौका मिलना चाहिए, यह इंसानी सोच उसे मजदूरों की हड़ताल का हिस्सा बना देती है।

हड़ताल अभी चल ही रही है कि एक इतवार मजदूरों को घिरी हुई सी एक जगह पर बातचीत के लिए बुलाया जाता है, जिसके किनारे-किनारे मौजूद मकानों की छतों पर देश की फौज ने मशीनगनें लगा रखी हैं। फिर बिना किसी चेतावनी के मशीनगनें चलने लगती हैं, जैसे गेहूं की मंड़ाई हो रही हो। लोग गिरते दिखाई देते हैं लेकिन तड़-तड़ के सिवा कोई आवाज नहीं, एक कराह भी नहीं। देर रात गए जोस अर्कादियो की बेहोशी टूटती है तो वह खुद को खुले डिब्बों वाली एक बहुत लंबी मालगाड़ी में लाशों के नीचे दबा पाता है, जो अपनी बत्ती बुझाए हुए समुद्र की दिशा में दौड़ी चली जा रही है।

फिर अचानक याद आता है कि पीठ में बुलेट धंसने और होश खोने तक अस्पष्ट हाहाकार से पहले उसने एक अकेली लंबी चीख सुनी थी। किसी तरह ट्रेन से उतरकर बहुत लंबे सफर के बाद जोस वापस अपनी बस्ती पहुंचता है और यह जानकर हैरान हो जाता है कि इस जनसंहार के बारे में वहां कोई कुछ नहीं जानता। सरकारी रेडियो ने लोगों को यही बताया है कि मजदूरों की सारी मांगें मान ली गईं, उन्होंने अपनी पगार पकड़ी और अपने-अपने घर चले गए। जोस का पूरा जीवन जनसंहार के सबूत जुटाने में गुजर जाता है लेकिन खुद को भरोसेमंद बनाने का काम उससे नहीं हो पाता!

गतांक की चीर-फ़ाड़

संघ परिवार के लिये विशेष डेमोक्रेसी

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 13-19 दिसम्बर 2020 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक ज्वलंत मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। कोरोना आपदा को अवसर में बदलते हुए मोदी सरकार द्वारा पारित तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ़ चल रहे देश-व्यापी अहिंसक व अनुशासित किसान आंदोलन ने कृषि का भविष्य किसानों की सुरक्षा, कृषि भूमि व उत्पाद के लागत मूल्य के मुद्दों को राजनीति के केन्द्र में ला दिया है तथा मोदी सरकार के निरंकुश शासन को किसानों से बात-चीत करने के लिये मजबूर कर दिया है। 'मोदी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसानों ने पकड़ा, लाचार भक्त रह गये फ़ड़फड़ाते' में कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान आंदोलन, धरना-प्रदर्शन व दिल्ली के बार्डर पर नाकाबंदी की समीक्षा की गई है।

नि:संदेह किसान आंदोलन वास्तव में एक जन- आंदोलन का रूप ले चुका है और मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ़ लोगों में भारी रोष है। आन्दोलनकारी किसानों के साथ आम जनता जुड़ती जा रही है। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशों में किसान आन्दोलन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि भारत के 22 पूर्व राजनयिकों ने कनाड़ा के प्रधानमंत्री द्वारा किसान आन्दोलन के समर्थन में दिए बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई है। जबकि यूएन के महासचिव ने भी किसान आन्दोलन के समर्थन में बयान दिया है।

पूरा देश बिना किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय व क्षेत्रीय भेदभाव के किसानों के साथ लामबंद हो गया है। मोदी सरकार के सीएए व एनआरसी केखिलाफ़ शाहीन बाग आन्दोलन के बाद किसान आन्दोलन ने एक बार फ़िर प्रमाणित कर दिया है कि भारत में धर्म निरपेक्षता की जड़ें बहुत गहरी है, जिसका 'भारत के डीएनए को बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है' में विवेचन किया गया है। पंजाब के मलेरकोटला से आए मुसलमानों के जत्थे द्वारा सिंघु बार्डर पर किसान आन्दोलन के धरना-प्रदर्शन स्थल पर लंगर शुरू करते ही भाजपा के आईटी सेल ने आंदोलन फूट डालने के लिये मुसलमान जत्थे के खिलाफ़ जहर उगलना व निंदा अभियान शुरू कर दिया। लेकिन भाजपा के इस चिर-परिचित हथकंडे का आन्दोलनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ।

दरअसल संघ परिवार के लिये वह सब डेमोक्रेसी है जो मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना या विरोध करे। संघ परिवार अब मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी का नया संदेशवाहक बन गया है।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हर जिले में पार्टी दफ्तर बनाने के निर्णयानुसार भाजपा के साथ-साथ जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) भी हरियाणा के हर ज़िले में अपना दफ्तर बनाना चाहती है। फ़रीदाबाद शहर में एक प्लॉट पर दोनों पार्टियों द्वारा अपना दफ्तर बनाने को लेकर रस्सा-कस्सी चल रही है, जिसका 'हुडा फ़रीदाबाद:एक प्लॉट के दो बीमार-राज्य में भाजपा और जेजेपी को प्लॉट बांटने में कई जगह नियम ताक पर रखे गए' में पर्दाफ़ाश किया गया है।

विडम्बना है कि कांग्रेस शासनकाल में कांग्रेस समर्थित नेशनल हेराल्ड और नवजीवन के लिए पंचकूला में जमीन आवंटित करने को लेकर भाजपा हमेशा कांग्रेस पर आक्रामक रही है, जबकि अब हरियाणा हर ज़िले में भाजपा और जेजेपी के दफ़्तर के लिये जमीन आवंटित की जा रही है।

नए कृषि कानूनों से कॉरपोरेट कृषि व्यवस्था को बढावा मिलेगा जो कृषि और किसानों को जड़ों से अस्थिर करने वाली प्रणाली है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर आंदोलनकारी किसानों व सरकार के बीच सहमति न बन पाने से बौखलाकर मोदी सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने के हर हथकंडे अपना रही है, जिसको 'कॉरपोरेट कृषि से अपराधीकरण की सुनामी आ सकती है' तथा किसानों को ऐसे बता रहे हैं खालिस्तानी' में बेनकाब किया गया है।

मोदी सरकार ने किसान आन्दोलन से निपटने के लिये टकराव की रणनीति अपना ली है। इसलिए मोदी सरकार, आरएसएस, भाजपा तथा मोदी समर्थक मीडिया द्वारा बड़े योजनाबद्ध तरीके से आन्दोलनकारियों को उकसाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन्हें राष्ट्रविरोधी, खालिस्तानी, अलगाववादी, माओवादी, नक्सली, अल्ट्र लेफ्टिस्ट, टुकड़ा-टुकड़ा गैंग तथा विपक्ष द्वारा भ्रमित करार दिया जा रहा है और उनके आंदोलन को पाकिस्तान व चीन द्वारा प्रेरित बताया जा रहा है। सरकार की रणनीति यह भी है कि मौजूदा आंदोलन को महज पंजाब के किसानों का आंदोलन बना कर पेश किया जाए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास करते हुए कहा कि यह भवन भारतीय प्रजातांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर सावित होगा तथा 21 वी शताब्दी के भारत व आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा तथा पूरी दुनियां बहुत जल्द भारत को 'मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी' लोकतंत्र की जननी कहेगी। दूसरी तरफ़ नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत के अनुसार भारत में इतना ज्यादा लोकतंत्र (टू मच डेमोक्रेसी)है कि कोई ठीक काम हो ही नहीं सकता। 'मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी+ डेमोक्रेसी=मोदीक्रेसी' में मोदी सरकार की विफ़लताओं का खुलासा किया गया है।